कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Postal R.No.MP/BPL/525/2025-27 RNI No. Raj HIN/2000/3239, डाक प्रेषण का दिन- मंगलवार, बुधवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर

ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 जयपुर, प्रकाशन सोमवार, 19 जनवरी 2026 वर्ष-26 अंक-17 मूल्य-12/- कुल पृष्ठ-12 www.krishakjagat.org पृष्ठ-1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

भाकृअनुप ICAR

अंदर पढ़िये...

5

प्राकृतिक खेती आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) - 2026' के संबंध में ली समीक्षा बैठक

किसानों को हर क्षेत्र में उन्नत एवं खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

जयपुर। प्रदेश में आयोजित होने वाली 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026' से पूर्व गिरदावर सर्किल स्तर पर 23 जनवरी (बसंत पंचमी) से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीट में अधिक से अधिक कृषकों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित करने और उन्हें धरातल पर विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये शिविर महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

श्री शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व है क्योंकि यह रबी फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो अच्छी पैदावार और समृद्धि की उम्मीद जगाती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 22 जनवरी को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को शिविरों के आयोजन के संबंध में जानकारी दी जाए।

प्रदेश में गिरदावर सर्किल स्तर पर इन शिविरों का आयोजन 23, 24, 25 व 31 जनवरी तथा 1, 5, 6, 7 व 9 फरवरी को किया जाएगा। शिविरों में विकसित भारत-रोजगार और वीबी - जी राम जी के तहत गांवों में आवश्यक विकास कार्यों के प्रस्ताव लेने के साथ ही स्वॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना के तहत पॉलिसी वितरण, पॉलीहाउस की स्वीकृति, पशु टीकाकरण सहित कृषि एवं उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर क्षेत्र में उन्नत एवं खुशहाल बनाने के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 का आयोजन करने जा रही है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

अब घटिया बीज बेचने वालों को 30 लाख तक जुर्माना, कड़ी सजा : श्री चौहान

कोई भी अनधिकृत विक्रेता बीज नहीं बेच पाएगा

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नए सीड एक्ट (Seed Act 2026) की विशेषताओं और उसके किसानों पर होने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक कदम है।

हर बीज की पूरी कहानी किसानों तक

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब देश में बीज की ट्रेसिबिलिटी की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया, 'हमने कोशिश की है कि ऐसा सिस्टम बने, जिसमें यह पूरा पता चल सके कि बीज कहां उत्पादित हुआ, किस डीलर ने दिया और किसने बेचा।' हर बीज पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही किसान यह जान सकेगा कि वह बीज कहां से आया है। इससे घटिया या नकली बीज न केवल रोके जा सकेंगे बल्कि यदि वे बाजार में आएंगे भी तो जिम्मेदार व्यक्ति पर शीघ्र कार्रवाई संभव होगी।

घटिया बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि जैसे ही ट्रेसिबिलिटी लागू होगी, नकली या खराब बीज की पहचान तुरंत हो जाएगी। उन्होंने कहा, 'खराब बीज आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो पकड़े जाएंगे। जिसने खराब बीज दिया, उसे दंड दिया जाएगा।' इससे किसानों को भ्रमित करने वाली कंपनियों और डीलरों की मनमानी पर लगाम लगेगी।

30 लाख तक जुर्माना और सजा

श्री चौहान ने कहा कि बीजों की गुणवत्ता पर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।, 'अभी तक 500 रुपये तक का जुर्माना था, अब प्रस्ताव है कि 30 लाख रुपये तक जुर्माना हो और अगर कोई जानबूझकर अपराध करता है तो सजा का भी प्रावधान है।' उन्होंने कहा कि सब कंपनियां खराब नहीं हैं, लेकिन जो किसान को धोखा देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सर्वोत्तम गुणवत्तावाली
जैन ड्रिप की विस्तृत उत्पादन श्रृंखला -
सभी फसलों # के लिए हर किसान के बजट के
अनुरूप विभिन्न प्रकार के ड्रिप सिचाई व्यवस्था
के विकल्प स्टॉक में उपलब्ध हैं।
(# दलहन, धान, तिलहन, सब्जियाँ एवं फल बागानें आदि के लिए)

नोट : ड्रिपर्स व ड्रिपलाईन अलग-अलग प्रेशर रेटींग में उपलब्ध

जैन ड्रिप® प्रति बूँद, फसल भरपूर!®
जैन इरिगेशन सिस्टम्स् लि. छोटे छोटे कदम, आसमान छूने का दम!®
दूरभाष: 0257-2258011; 6600800
टोल फ्री : 1800 599 5000
ई-मेल: jisl@jains.com; वेबसाईट: www.jains.com

ड्रिपलाईन व फिटींग्ज | ड्रिपर्स | रेनपोर्ट स्प्रिंकलर | स्प्रे हेड व जेटस् | वॉल्व | फिल्टर्स | फिल्ट्रेशन संसाधन | फर्टिगेशन संसाधन | पीव्हीसी पाईप व फिटींग्ज | एचडीपीई पाईप्स व फिटींग्ज | क्विक कनेक्ट पाइप | ऑटोमेशन व कन्ट्रोलर्स

सावधान! नकल करके ड्रिप बनाने वाले एवं
नकली ड्रिप कंपनियों और वितरकों से सतर्क रहें!

2047 तक सभी देसी पशु नस्लों का 100 फीसदी पंजीकरण लक्ष्य : श्री चौहान

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) द्वारा नई दिल्ली में पशु नस्ल पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं नस्ल संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2047 तक सभी देसी पशु नस्लों का 100 प्रतिशत पंजीकरण करना भाकृअनुप का लक्ष्य है, जो विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने देसी पशु नस्लों के संरक्षण को पर्यावरण, किसानों की आजीविका और सतत कृषि से जुड़ा बताते हुए इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने पर ज़ोर दिया।

देसी पशुधन खेती की अर्थव्यवस्था की रीढ़

केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2019 में शुरू की गई देसी पशु नस्ल संरक्षण की राष्ट्रीय पहल को एक सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि देसी मवेशी, भैंस, मुर्गी और छोटे जुगाली करने वाले पशु देश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

पॉलिसी से आगे बढ़े जन आंदोलन

श्री चौहान ने कहा कि पशु नस्ल संरक्षण का यह मिशन केवल नीति और सम्मेलनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे गांवों, खेतों और किसान परिवारों तक पहुंचाकर जन आंदोलन बनाना होगा।

242 पशु नस्लें पंजीकृत, लक्ष्य 100 प्रतिशत

इस अवसर पर भाकृअनुप के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने कहा कि 'विकसित भारत – पशुधन' का विज़न संरक्षण के साथ-साथ संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग पर केंद्रित है।

उन्होंने बताया कि 2008 से अब तक 242 पशु नस्लों का पंजीकरण किया जा चुका है। 2047 तक सभी देसी पशु नस्लों का शत-प्रतिशत पंजीकरण भाकृअनुप का लक्ष्य है।

नस्ल संरक्षण पुरस्कार वितरित

कार्यक्रम में नई पहचानी गई पशु एवं पोल्ट्री नस्लों को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए तथा वर्ष 2025 के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार से किसानों, ब्रीडर्स और संस्थानों को सम्मानित किया गया।

सस्टेनेबल पशुधन विकास का संदेश

कार्यक्रम में उप-महानिदेशक (पशुविज्ञान) डॉ. राघवेंद्र भट्टा ने पंजीकृत नस्लों की जानकारी देते हुए उनके संरक्षण को सस्टेनेबल पर्यावरण के लिए आवश्यक बताया।

बजट पूर्व कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े सुझावों की रिपोर्ट सौंपी केंद्रीय कृषि मंत्री ने

श्री चौहान ने वित्त मंत्री से की मुलाकात

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दिल्ली में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। श्री चौहान ने हाल के सप्ताहों में देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया और राज्यों के अलावा दिल्ली में भी प्रगतिशील किसानों, कृषि विशेषज्ञों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण उद्योगों एवं दोनों मंत्रालयों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से व्यापक संवाद स्थापित किया। इन चर्चाओं से प्राप्त विचारों और सुझावों को एक समग्र कृषि एवं ग्रामीण विकास के सुझाव के रूप में तैयार कर उन्होंने वित्त मंत्री को सौंपा।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। श्री चौहान ने कहा कि आगामी आम बजट किसानों और ग्रामीण समाज के लिए प्रेरक होगा। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रधानमंत्री के 'समृद्ध किसान, सशक्त गांव' के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

आईसीएआर-एनडीडीबी के बीच समझौता

आईसीएआर ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य संपूर्ण डेयरी क्षेत्र में बहुविषयक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाना है। इस समझौता ज्ञापन पर आईसीएआर के उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) डॉ. राघवेंद्र भट्टा और एनडीडीबी के कार्यकारी निदेशक श्री एस. रेगूपथी ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट और एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

आईपीएम पर प्रशिक्षण से किसानों तक पहुंचेगी सही तकनीक

नासिक (कृषक जगत)। भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के उपक्रम केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र, नासिक द्वारा सब्जी फसलों में 'एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन' (IPM) पर एक महीने का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के 40 कृषि अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य- इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषि अधिकारियों को आईपीएम की आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करना था ताकि वे किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने और टिकाऊ सब्जी उत्पादन अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।

समापन समारोह में प्रमुख हस्तियां- समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. सुनीता पांडेय, संयुक्त निदेशक, आईपीएम एवं टिड्डी विभाग, फरीदाबाद ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से राज्य और केंद्र के कृषि अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे किसानों तक सही तकनीक पहुंचाई जा सकेगी। विशिष्ट अतिथि श्री मुकेश महाजन, सहायक निदेशक, रामेती नासिक और डॉ. मनीष मोंढे, उप निदेशक, केंद्रीय आईपीएम केंद्र, नागपुर भी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण की मुख्य बातें- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सब्जी उत्पादन में कीट, रोग और खरपतवार प्रबंधन पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। डॉ. सुनीता पांडेय ने कहा कि इस प्रशिक्षण से किसानों को रासायनिक कीटनाशकों के अवशेष की समस्या से निजात दिलाई जा सकेगी।

एनपीएसएस मोबाइल ऐप- कृषि अधिकारियों को एनपीएसएस मोबाइल ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे किसान कीट और रोग की पहचान कर तुरंत प्रबंधन सलाह ले सकते हैं। केंद्रीय आईपीएम केंद्र के कार्यालय प्रमुख डॉ. अतुल ठाकरे ने कहा इस प्रशिक्षण से जमीनी स्तर पर टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा।

देश में रबी का रकबा 644 लाख हेक्टेयर से अधिक

नई दिल्ली (कृषक जगत)। देश में रबी मौसम 2025-26 की बुवाई अब निर्णायक चरण में पहुँच चुकी है। कृषि मंत्रालय द्वारा 9 जनवरी 2026 तक जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, देश में कुल रबी फसलों का क्षेत्रफल 644.29 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। यह रकबा पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17.65 लाख हेक्टेयर अधिक है।

गेहूं: रबी सीजन की सबसे अहम फसल गेहूं एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। गेहूं की बुवाई 334.17 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 328.04 लाख हेक्टेयर से 6.13 लाख हेक्टेयर अधिक है।

रबी चावल: इस सीजन में रबी चावल की बुवाई 21.71 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह 19.49 लाख हेक्टेयर थी।

दलहन: देश में दलहनों का कुल रकबा 136.36 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.74 लाख हेक्टेयर अधिक है। यह वृद्धि लगभग 2.8 प्रतिशत की है। दलहनों में चना सबसे आगे रहा है, जिसमें 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

श्री अन्न और मोटे अनाज: श्री अन्न और मोटे अनाजों का कुल क्षेत्र 55.20 लाख हे. रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.03 लाख हे. अधिक है। खासतौर पर जौ और मक्का ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

तिलहन: रबी सीजन 2025-26 में तिलहन फसलों का रकबा 96.86 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष से 3.5 लाख हेक्टेयर अधिक है। यह लगभग 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा अलसी, कुसुम और सूरजमुखी में भी विस्तार देखने को मिला है।

प्रमुख रबी फसलों की बुवाई
9 जनवरी 2026 की स्थिति (लाख हे. में)

फसल	सामान्य क्षेत्र	बुवाई 2025-26	बुवाई 2024-25
गेहूँ	**312.35**	**334.17**	**328.04**
चावल	**42.93**	**21.71**	**19.49**
दालें	**140.42**	**136.36**	**132.61**
चना	100.99	95.88	91.22
मोटे अनाज	**55.33**	**55.20**	**53.17**
ज्वार	24.62	21.36	22.66
मक्का	23.61	25.24	23.49
तिलहन	**86.78**	**96.86**	**93.33**
सरसों	79.17	89.36	86.57
कुल	**637.81**	**644.29**	**626.64**

नोट : कुल क्षेत्रफल के आंकड़े चार्ट से अलग हैं, क्योंकि सभी फसलों को चार्ट में शामिल नहीं किया गया है। स्रोत : कृषि मंत्रालय

अब घटिया बीज बेचने वालों को... (पृष्ठ 1 का शेष)

बीज कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

श्री चौहान ने कहा कि अब हर सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे यह साफ रहेगा कि कौन सी कंपनी अधिकृत है। उन्होंने कहा, 'पंजीकृत कंपनियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी और कोई भी अनधिकृत विक्रेता बीज नहीं बेच पाएगा।'

परंपरागत बीजों पर कोई पाबंदी नहीं

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने इस भ्रम को दूर किया कि नया कानून किसानों के परंपरागत बीजों पर रोक लगाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा, 'किसान अपने बीज बो सकते हैं, दूसरे किसान को बीज दे सकते हैं। स्थानीय स्तर पर जो परंपरागत बीज विनिमय की परंपरा है, वो जारी रहेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।'

ICAR और देसी कंपनियां रहेंगी मैदान में मजबूत

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि सीड एक्ट में तीनों स्तर पर प्रावधान किए गए हैं- सार्वजनिक क्षेत्र (ICAR, कृषि विश्वविद्यालय, KVKs), देसी कंपनियां जो उच्च गुणवत्ता के बीज बनाती हैं, विदेशी बीजों के लिए उचित मूल्यांकन व्यवस्था। उन्होंने कहा, 'विदेश से आने वाले बीज पूरी तरह जांच और मूल्यांकन के बाद ही स्वीकृत होंगे। हमारे सार्वजनिक और देसी निजी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा ताकि किसानों तक अच्छे बीज पहुंचें।'

सवाई माधोपुर में 150 करोड़ रुपये की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाया जाएगा

अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला-2026

राजस्थान के अमरूद से किसानों की आमदनी सालाना करीब 600-700 करोड़ रुपये

सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का अमरूद आने वाले दिनों में क्षेत्र के किसानों की जिन्दगी में बेहतरी लाएगा। राज्य सरकार द्वारा जिले में अमरूद का प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाया जाएगा, जिससे देश-विदेश में इस फल और इससे बने उत्पादों की मांग बढ़ेगी। देश में पहली बार आयोजित अमरूद महोत्सव इस दिशा में प्रयासों का पहला कदम है। इसके सुखद परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और राज्य के कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण विकास एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दशहरा मैदान में अमरूद महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में यह बात कही। लोकसभा अध्यक्ष सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला-2026 के मुख्य अतिथि थे। कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास आपदा प्रबन्धन मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा आयोजन की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की किसानों की आमदनी बढ़ाने की सोच के अनुसार काम करते हुए राज्य सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इन्ही प्रयासों की कड़ी में सवाई माधोपुर में भारत में पहली बार अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश-प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से किसानों, कृषि उत्पाद व्यापारियों और कृषि यंत्र एवं तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों को साझा मंच उपलब्ध कराया गया है, ताकि वे अपने अनुभवों को साझा कर उन्नत कृषि को अपना सकें।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बेशक अमरूद एक सस्ता फल है, लेकिन बहुत अधिक स्वास्थ्य-वर्धक है। अमरूद महोत्सव जैसे आयोजन के जरिए लोगों को इस फल के स्वास्थ्य से जुड़े लाभों के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे बनने वाले अचार, जूस, पल्प, मिठाई आदि भी इस मेले में प्रदर्शित किए गए है। उन्होंने कहा कि यहां अमरूद के लाभ, इसकी खेती की नई तकनीक और उन्नत किस्मों तथा प्रसंस्करण की विधियों की जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने महोत्सव के दौरान सवाई माधोपुर में अमरूद का प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने की घोषणा की है। जब किसी कृषि उत्पाद का संवर्धन होता है, तभी किसान की वास्तविक आय बढ़ती है। इस प्रकार यह आयोजन क्षेत्र के अमरूद के किसानों की जिन्दगी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री डॉ. मीणा ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही सवाई माधोपुर की धरती पर 150 करोड़ रुपये की लागत से अमरूद का प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित करेगी। राजस्थान में कुल 14 हजार हेक्टेयर अमरूद के बगीचों में से 11 हजार हेक्टेयर अकेले इस जिले में हैं। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर का अमरूद यहीं पर खपने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार की है।

डॉ. मीणा ने कहा कि राजस्थान के अमरूद के किसानों की इस फल से आमदनी सालाना करीब 600-700 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की किसानों की आय बढ़ाने की मंशा के अनुरूप हमारा लक्ष्य अमरूद से आमदनी को 1500-1600 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष करना है।

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में सवाई माधोपुर में 600 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य करवाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानसून के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों का काफी नुकसान हुआ। इससे बचाव के लिए सूरवाल बांध के पानी को बनास नदी में छोड़ने के लिए 110 करोड़ रुपये की लागत से एक चैनल बनाया जाएगा। इससे जिले में सिंचाई के लिए भी अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

डॉ. मीणा ने अमरूद महोत्सव में आए किसानों और अन्य प्रतिभागियों से इस आयोजन का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान कृषि यंत्रों, बागवानी, उत्पादों के प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों और वैज्ञानिकों आदि के साथ संवाद करें और यहां लगी लगभग 250 स्टॉल्स को देखकर एक दूसरे से उन्नत कृषि की तकनीकी और किस्मों की जानकारी प्राप्त करें।

कार्यक्रम को जिला कलक्टर काना राम, पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने भी सम्बोधित किया। अतिरिक्त निदेशक कृषि देशराज ने आभार व्यक्त किया।

कृषि विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर यूरिया प्राप्त करना सुनिश्चित करें किसान

श्रीगंगानगर। इस वर्ष रबी सीजन में नहरी सिंचाई पानी की समय पर उपलब्धता के चलते गेंहू, सरसों एवं जौ के क्षेत्रफल में इजाफा होने की संभावना के मद्देनजर जिला श्रीगंगानगर में रबी 2025-26 हेतु 150000 मैट्रिक टन यूरिया उर्वरक की मांग कृषि आयुक्तालय को भिजवाई गई। इस सीजन में बीते माह दिसम्बर तक 108000 मैट्रिक टन यूरिया उर्वरक की मांग के विरूद्ध अभी तक 113549 मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति जिले में हो चुकी है। कृषि (विस्तार) संयुक्त निदेशक ने बताया कि 10 जनवरी 2026 को जिले की सूरतगढ़ मंडी में 2185 बैग, श्रीविजयनगर 15000 बैग, रामसिंहपुर 3650 बैग एवं अनूपगढ़ मंडी में 8500 बैग यूरिया का वितरण कृषि विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की देखरेख में टोकन के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक करवाया गया है। एक ही किसान बार-बार लाईन में न लगे, यह सुनिश्चित करने हेतु परमानेंट मार्कर से अंगुली पर निशानदेही की गई। श्रीविजयनगर मण्डी में 10000 बैग यूरिया का स्टॉक मौजूद है, जिसे कल टोकन वितरण कर किसानों में वितरण किया जावेगा। जिले में 7650 मैट्रिक टन बैग यूरिया के और पहुंचने की संभावना है। इनका वितरण भी पूर्ण पारदर्शिता से करवाने हेतु कृषि एंव राजस्व विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस रबी सीजन में नहरी सिंचाई पानी की समय पर उपलब्धता के चलते गेहूं, सरसों एवं जौ के क्षेत्रफल में इजाफा होने एवं वर्तमान में फसल स्थिति अच्छी होने के कारण क्षेत्र में यूरिया की मांग में वृद्धि हुई है।

किसानों को हर क्षेत्र में उन्नत... (पृष्ठ 1 का शेष)

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों के सफल आयोजन के लिए कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, सिंचाई सहित सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर कृषकों एवं पशुपालकों सहित ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाएं।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में देश-विदेश के कृषक एवं विशेषज्ञ होंगे शामिल- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मीट के राज्य स्तरीय आयोजन में देश-विदेश के किसान, पशुपालक हिस्सा लेंगे। साथ ही, कृषि एवं पशुपालन की उन्नत तकनीक साझा करने के लिए देश-विदेश से विभिन्न प्रदर्शक फर्म भी आएंगी। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का भी ग्राम-2026 में सम्मान किया जाए। साथ ही, देश-विदेश में उन्नत कृषि, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण जैसे नवाचारों को उपयोग में लाने वाले कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों तथा तकनीकी जानकारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे ग्रामीण स्तर पर किसानों को कार्यक्रम एवं योजनाओं की जानकारी मिल सके।

बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से किया संवाद

किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार गंभीर

जयपुर। प्रदेश में कृषकों के कल्याण को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के तहत पंत कृषि भवन में कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ी लाल ने प्रदेश के विभिन्न किसान संघों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। संवाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषक आदान-अनुदान, नवीन बीज विधेयक, पेस्टीसाइड्स मैनेजमेंट बिल सहित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से संबंधित योजनाओं तथा बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषक आदान-अनुदान योजनाओं के अंतर्गत देय राशि में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसान संगठनों द्वारा बीमा कंपनियों के संबंध में की गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगने तथा लंबित क्लेम प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि किसान संगठनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर योजनाओं को और अधिक किसान हितैषी बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल बीमा एवं आदान-अनुदान से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए। संवाद के दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों में लंबे समय से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और उन्हें शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए।

किसानों द्वारा खेतों में जंगली सूअर एवं निराश्रित पशु से होने वाले नुकसान की शिकायत के संबंध में कृषि मंत्री ने बताया कि इस विषय में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही, तारबंदी योजना में आवश्यक संशोधन के लिए भी कार्य प्रस्तावित है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज एवं खाद का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाए एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही की शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर किसान संघों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं, सुझाव एवं अपेक्षाएं रखीं, जिस पर कृषि मंत्री ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल, कृषि आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल, उद्यानिकी आयुक्त श्रीमती शुभम चौधरी, कृषि एवं उद्यानिकी, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्य अधिकारी तथा बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार बोन्द्रिया द्वारा संदीप शर्मा मे. संदीप इन्टरप्राइजेस, एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित एवं पेपर प्रिंट इंडस्ट्रीज 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, सम्पादक : सुनील गंगराड़े, समन्वयक : रीतेश कोंडले. इस अंक का मूल्य रुपये 12/- वार्षिक शुल्क रुपये 600/- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रं. Raj/HIN/2000/3239

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्द्रिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

जिसको रहस्य गोपनीय रखना नहीं आता
वह सफलता का मुंह नहीं देख सकता। - चाणक्य

अन्नदाता आयुष्मान भवः !

कृषि प्रधान देश भारत में किसानों को 'अन्नदाता' के नाम से भी सम्बोधित करते हैं और अन्नदाताओं ने भी उन्हें दिये गए सम्मान का मान रखते हुए देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में दलहन और खाद्य तेलों को छोड़कर आत्मनिर्भर बना दिया है। देश में करीब 14 करोड़ किसान हैं। अधिक उत्पादन के लिए कृषि भूमि और फसलों में रासायनिक खादों और जहरीली दवाईयों के अत्यधिक प्रयोग से जहां एक ओर कृषि भूमि की उर्वराशक्ति लगभग समाप्त हो गई है वहीं दूसरी ओर किसान भी इनके दुष्प्रभावों से प्रभावित हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप कैंसर, रक्तचाप, थायराईड, मधुमेह, पैरालाईसिस जैसी अनेक बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ईलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हैं लेकिन चिकित्सा की सुविधाएं बहुत कम होती हैं। सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 31,882 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 6,359 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1.69 लाख उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। कुछ उप स्वास्थ्य केंद्रों के पास अपने निजी भवन भी नहीं है और वे किराए या पंचायत भवन से चल रहे हैं। सामान्य क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर औसतन 30 हजार ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का मापदण्ड है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की निरंतर कमी रहती है और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव बना रहता है इसलिए शहरों में शासकीय और निजी अस्पतालों में ग्रामीण मरीजों की संख्या भी अधिक रहती है।

जब से केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है, यह योजना देश के गरीब और वंचित वर्ग के लिए संजीवनी बनकर सामने आई है। इस योजना में कमजोर परिवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया गया है अर्थात् पांच लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज कराया जा सकता है। इससे देश के करीब 50 करोड़ पात्र लाभार्थियों को देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त हो रही है। यह सही है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से विशेषकर गरीबों को इलाज पर होने वाले खर्च से राहत मिल रही है। इस योजना का यह उजला पक्ष है जिससे यही महसूस होता है कि यह गरीबों के लिए वरदान है लेकिन इसके स्याह पक्ष पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । भोले - भाले ग्रामीण गरीब और किसान जब इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं तो अनावश्यक जांच और आपरेशन कर देने

की घटनाएं बढ़ने और सुनने को मिल रही हैं। जब निःशुल्क इलाज हो रहा है तब मरीज भी आसानी से आपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। देशभर में ऐसे हजारों की संख्या में प्रकरण सामने आये हैं जिनमें आवश्यकता नहीं होने पर भी आपरेशन कर दिया जाता है। इससे भले ही आपरेशन या इलाज का कोई खर्च नहीं देना होता लेकिन अनावश्यक रूप से किए गए आपरेशन का मरीज के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है और काफी संख्या में मरीजों को जीवन पर्यंत दवाईयों/बैसाखी के सहारे ही जीवन गुजारना पड़ रहा है।

कुछ अस्पतालों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने और वहां चिन्हित तथाकथित मरीजों को आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज करने का आश्वासन दिया जाता है। जागरूकता और बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण ग्रामीणजन अस्पताल में भरती हो जाते हैं और अस्पताल प्रबंधन अपनी मरजी से इलाज करते हैं जब तक कि आयुष्मान योजना की राशि समाप्त न हो जाए। इससे यही प्रतीत हो रहा है कि क्या आयुष्मान योजना वास्तव में गरीबों को इलाज दिला रहा है या फिर कहीं यह इलाज के नाम पर धोखाधड़ी का माध्यम तो नहीं बनता जा रहा है ? मरीज को पूरी जानकारी दिए बिना ही पैकेज का उपयोग और कागजों पर इलाज दिखाने के भी प्रकरण सामने आ रहे हैं। वहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई पात्र गरीब आज भी योजना के लाभ से वंचित हैं। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अनेक निजी अस्पताल इलाज करने से मना कर देते हैं। कहीं बेड उपलब्ध न होने का बहाना बनाया जाता है, तो कहीं इलाज के लिए अतिरिक्त पैसे माँगे जाते हैं। गरीब मरीज मजबूरी में या तो स्वयं खर्च उठाता है या इलाज अधूरा छोड़ देता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहाँ गरीब सिर्फ नाम का लाभार्थी बना और असली फायदा अस्पतालों ने उठा लिया।

अब जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए जिसमें इस योजना के प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सर्वसुविधायुक्त बनाने और चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि मरीज का वहीं इलाज हो जाए जिससे आयुष्मान योजना का दुरूपयोग न हो। आपात स्थिति को छोड़कर मरीजों को निजी अस्पताल में भरती करने के पूर्व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से रेफर कराने से भी योजना के दुरूपयोग पर आंशिक रोक लगाई जा सकती है। योजना के कार्यांवयन की निगरानी, अस्पतालों के दावों की समय पर जाँच, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ग्रामीण स्वास्थ्य को केवल एक विभागीय जिम्मेदारी न मानकर सामाजिक प्राथमिकता बनाने की आवश्यकता है। चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रोत्साहन, बेहतर अधोसंरचना, डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग करके ही ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य समाधान दे सकते हैं। अब किसानों को भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि बीमार होने के प्रमुख कारण क्या हैं? कृषि भूमि में रासायनिक खादों और फसलों में जहरीली दवाओं का अत्यधिक उपयोग भी एक कारण हो सकता है। उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन पोषक तत्वों की कमी हो गई है। इन सब कारकों पर व्यापक विचार विमर्श कर और इससे निकले निष्कर्ष पर इमानदारी से कार्यांवयन से ही स्वस्थ भारत का सपना साकार हो सकेगा।

गाँवों में एक तिहाई लोगों को स्वच्छ पानी मयस्कर नहीं

● डॉ. चन्दर सोनाने

मध्यप्रदेश के इन्दौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 18 लोगों की जान जाने के बाद अब एक और खबर आई है वह यह कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 36.7 प्रतिशत जगह नल का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर होने के दावे के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की यह खबर शर्मनाक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के हालात बयां करने वाली यह खबर केन्द्र सरकार की है। हाल ही में 4 जनवरी 2026 को जल जीवन मिशन की फंक्शनैलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 36.7 प्रतिशत पेयजल सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि पानी का हर तीसरा गिलास पीने योग्य नहीं पाया गया है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक साफ पानी पहुँचाने के दावे की हकीकत केन्द्र की उक्त रिपोर्ट में हाल ही में सामने आ गई है। केन्द्र सरकार ने सितम्बर-अक्टूबर 2024 में मध्यप्रदेश के 15 हजार से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से पीने के पानी के सैम्पल लिये थे। अनेक सैंपलों में बैक्टीरिया और रासायनिक गड़बड़ियाँ पाई गई। देश में सबसे स्वच्छ शहर इन्दौर जिले में 100 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन होने के बावजूद 33 प्रतिशत घरों में ही पीने योग्य पानी पहुँच रहा है! अनूपपुर और डिंडोरी जिले में तो और भी खराब हालत है। इन दोनों जिलों में एक भी सैम्पल सुरक्षित नहीं मिला। बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में 50 प्रतिशत से ज्यादा सैम्पल दूषित मिले। अन्य जिलों की भी कमोबेश यही स्थिति है। ये आँकड़े प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक है। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी और अत्यन्त महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के अंतर्गत 28 जुलाई 2024 तक देशभर में 78 प्रतिशत घरों में नल चालू है। किन्तु मध्यप्रदेश में क्वालिटी चेक की कमी के कारण हर साल हजारों लोग सुरक्षित पेयजल नहीं होने के कारण बीमार हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश की इस हालत को देखते हुए केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया तो 2026 में मिलने वाले आवंटन को घटाया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश की इस स्थिति को व्यवस्था जनित आपदा बताया है। देश के हर राज्य के ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को नल द्वारा शुद्ध पेयजल मिल सके इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मिशन है। किन्तु राज्यों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मध्यप्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो मध्यप्रदेश के सरकारी आँकड़ों के अनुसार 99.1 प्रतिशत गाँवों में हर घर जल योजना के तहत पाईप डाल दिए गए हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि 76.6 प्रतिशत घरों में ही सही तरीके से नल काम कर रहे हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हर चौथा घर अब भी इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित है। जल जीवन मिशन की फंक्शनैलिटी असेसमेंट रिपोर्ट में हर तीसरे घर में पीने का पानी सुरक्षित नहीं पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार 33 प्रतिशत घरों में नल का पानी गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गया है। यानी बड़ी आबादी को मिलने वाला पानी पीने के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त नल से दिये जाने वाले पीने के पानी की मात्रा भी तय मानक से कम पाई गई है। सरकारी मानक के अनुसार 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। किन्तु मध्यप्रदेश के 30 प्रतिशत घरों को यह तय मात्रा नहीं मिल पा रही है। कई क्षेत्रों में तो पानी रोज आता ही नहीं है। यहीं नहीं पानी प्रदाय का समय भी तय नहीं है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से दिए जाने वाले पानी पर लोगों का पूरा भरोसा भी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 63 प्रतिशत से ज्यादा परिवार पानी को उबालकर, छानकर या ट्रीट करने के बाद ही पानी का उपयोग करते हैं। यह सरकारी जल आपूर्ति प्रणाली पर भरोसे की कमी को भी दिखाता है। यही नहीं मध्यप्रदेश के 26.7 प्रतिशत स्कूलों में पानी का सैम्पल माइक्रोबॉयोलॉजिकल टेस्ट में फेल पाया गया है। अर्थात् स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला पानी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। केन्द्र सरकार की इस अत्यन्त महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन का उद्देश्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गाँवों के लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े और उन्हें अपने घर में ही नल से पानी मिल सके। इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या व्यवस्था की सामने आ रही है। इस मिशन में अब जो चुनौती आ रही है वह नल की नहीं है, बल्कि मेंटेनेंस, ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग की है। अनेक गाँवों में क्लोरीनेशन सिस्टम या तो है ही नहीं, या है तो वो पूरी तरह से सही काम नहीं कर रहा है। इसके साथ ही एक और कमी यह पाई जा रही है कि नल से मिलने वाले पानी के मासिक शुल्क की वसूली अत्यन्त कमजोर है। इससे मेंटेनेंस टिकाऊ नहीं बन पा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि देश में जल जीवन मिशन का अत्यन्त महत्व है। किन्तु इसके क्रियान्वयन में अनेक कमियों में एक महत्वपूर्ण कमी यह भी है कि गांवों में इस मिशन के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दे रखी है। इन दोनों विभाग में समुचित समन्वय नहीं होने से इस मिशन का पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारी भी पंचायत के अधीन नहीं है। पंचायतों के पास पर्याप्त आवंटन भी नहीं होता है, जिससे कि वे पानी को नियमानुसार ट्रीटमेंट कर सके और स्वच्छ जल प्रदाय कर सके। यदि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे स्टाफ को पूरी तरह पंचायत के अधीन कर दिया जाए, तो वे और सही तरीके से काम कर सकेंगे। आमजन की भी यह जिम्मेदारी है कि उन्हें जब अपने घरों में ही नल से पीने का पानी मिल रहा है तो वे भी नियमानुसार निर्धारित किया गया मासिक शुल्क समय पर जमा करें। इस पूरी व्यवस्था की नियमित समीक्षा भी आवश्यक है। इससे जहाँ भी कमी पाई जाए, उस कमी को समय पर दूर किया जा सके। यह सब होगा तो निश्चित रूप से जल जीवन मिशन अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा ऐसा ही चलता रहेगा !

प्राकृतिक खेती

आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता

● श्रीमती रिया ठाकुर
riyath29@gmail.com

मानव सभ्यता का इतिहास कृषि के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। कृषि ने ही मानव को भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान कर उसे स्थायी जीवन की ओर अग्रसर किया। किंतु आधुनिक युग में कृषि का स्वरूप तेजी से बदला है। अधिक उत्पादन की लालसा में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक तकनीकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया, जिससे अल्पकाल में तो उत्पादन बढ़ा, परंतु दीर्घकाल में इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आए। मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, जल और पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव आज एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुके हैं।

इन्हीं परिस्थितियों में प्राकृतिक खेती एक ऐसे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आई है, जो न केवल कृषि को टिकाऊ बनाती है, बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है। आज यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य चाहिए, तो कृषि को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा।

प्राकृतिक खेती की अवधारणा

प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है, जिसमें खेती को प्रकृति के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और कृत्रिम इनपुट्स का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि स्थानीय और प्राकृतिक संसाधनों- जैसे गोबर, गोमूत्र, फसल अवशेष, जैविक घोल तथा प्राकृतिक जैविक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है।

प्राकृतिक खेती का मूल दर्शन यह है कि मिट्टी स्वयं एक जीवंत तंत्र है, जिसमें असंख्य सूक्ष्मजीव, केंचुए और जैविक घटक मौजूद होते हैं। ये सभी मिलकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। जब रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, तो यह जीवंत तंत्र नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक खेती इसी तंत्र को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती है।

आधुनिक कृषि की समस्याएँ

आधुनिक रासायनिक कृषि ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। सबसे बड़ी समस्या मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की जैविक कार्बन मात्रा कम होती जा रही है, जिससे मिट्टी कठोर और कम उपजाऊ बनती जा रही है। इसके अतिरिक्त, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से लाभकारी कीट और सूक्ष्मजीव नष्ट हो रहे हैं। जल स्रोतों में रसायनों का बहाव जल प्रदूषण को बढ़ा रहा है, जिससे पेयजल संकट गहराता जा रहा है। मानव स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है। आज कई गंभीर बीमारियों का संबंध रसायनयुक्त भोजन से जोड़ा जा रहा है। इन सभी समस्याओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान कृषि प्रणाली दीर्घकाल तक टिकाऊ नहीं है।

प्राकृतिक खेती के प्रमुख घटक

प्राकृतिक खेती में कुछ प्रमुख तकनीकों और घटकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन (मल्चिंग), फसल चक्र, मिश्रित खेती और न्यूनतम जुताई प्रमुख हैं। ये सभी तकनीकें मिलकर मिट्टी, पौधों और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करती हैं।

बीजामृत बीजों को रोगों से बचाता है, जबकि जीवामृत मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ाता है। मल्चिंग से मिट्टी की नमी बनी रहती है और खरपतवार नियंत्रित होते हैं। फसल चक्र और मिश्रित खेती से कीट-रोगों का प्राकृतिक नियंत्रण संभव होता है।

जैव विविधता और प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब खेतों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, तो पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। इससे कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण होता है और रसायनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैव विविधता कृषि को अधिक लचीला और स्थायी बनाती है।

भारत में प्राकृतिक खेती की प्रासंगिकता

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में प्राकृतिक खेती का विशेष महत्व है। यहाँ अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके लिए महंगे रासायनिक इनपुट्स एक बड़ा बोझ हैं। प्राकृतिक खेती उन्हें कम लागत में खेती करने का अवसर प्रदान करती है। भारत सरकार और कई राज्य सरकारें भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही हैं। इससे किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती का क्षेत्रफल बढ़ रहा है।

चुनौतियाँ और समाधान

हालाँकि प्राकृतिक खेती के अनेक लाभ हैं, फिर भी इसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन में कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी और बाजार तक पहुँच जैसी समस्याएँ किसानों को हतोत्साहित करती हैं। इन चुनौतियों का समाधान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान, सरकारी समर्थन और उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। जब बाजार में प्राकृतिक उत्पादों की मांग बढ़ेगी, तो किसानों को उचित मूल्य भी मिलेगा।

भविष्य की दिशा

भविष्य की कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना अनिवार्य है। यह केवल कृषि पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करता है। यदि समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

प्राकृतिक खेती आज के समय की केवल एक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि भविष्य की अनिवार्यता है। यह मिट्टी, जल, पर्यावरण, किसान और उपभोक्ता सभी के हित में है। वर्तमान पर्यावरणीय संकट, बढ़ती उत्पादन लागत और स्वास्थ्य समस्याएँ हमें यह संकेत देती हैं कि अब कृषि को नई दिशा देने का समय आ गया है।

'प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर की गई खेती ही मानवता को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकती है और यही प्राकृतिक खेती का मूल संदेश है।'

प्राकृतिक खेती की आवश्यकता

मिट्टी संरक्षण के लिए

मिट्टी कृषि की आत्मा है। यदि मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी, तो कृषि भी स्वस्थ नहीं रह सकती। प्राकृतिक खेती मिट्टी की जैविक संरचना को पुनर्स्थापित करती है। जैविक पदार्थों के उपयोग से मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे पोषक तत्वों का चक्र सुचारु रूप से चलता है। इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है और वह लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है।

जल संरक्षण और जल गुणवत्ता

आज भारत सहित विश्व के कई देशों में जल संकट गहराता जा रहा है। प्राकृतिक खेती में मल्चिंग और जैविक पदार्थों के उपयोग से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। साथ ही, रसायनों के अभाव में जल स्रोत प्रदूषित नहीं होते। यह पद्धति भू-जल संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होती है।

पर्यावरण संतुलन

प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। यह वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करती है। इसके माध्यम से जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है। पक्षी, मधुमक्खियाँ और मित्र कीट प्राकृतिक खेती में सुरक्षित रहते हैं, जो फसल उत्पादन में सहायक भूमिका निभाते हैं।

मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा

आज के समय में स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता बन गया है। रसायनयुक्त भोजन मानव शरीर में धीरे-धीरे विष का संचय करता है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त खाद्य पदार्थ विषमुक्त और अधिक पौष्टिक होते हैं। इससे न केवल रोगों का खतरा कम होता है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।

किसानों की आर्थिक स्थिति

प्राकृतिक खेती किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी है। इसमें बाहरी इनपुट्स पर निर्भरता कम होती है, जिससे उत्पादन लागत घटती है। किसान स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनता है। लंबे समय में यह खेती किसानों को स्थायी आय और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

● शिवानी ● दिव्यांशी दीक्षित ● विवेक यादव
फल विज्ञान विभाग, उद्यान महाविद्यालय
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, (उप्र)
मो.: 9411661462

ग्रीन हाउस में टमाटर की खेती

किसानों की आय का प्रमुख स्रोत

भारतीय कृषि लंबे समय से प्राकृतिक संसाधनों, मौसम की अनिश्चितता और बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर रही है। टमाटर जैसी नकदी फसल, जिसकी मांग पूरे वर्ष बनी रहती है, खुले खेतों में उगाने पर अक्सर किसानों के लिए घाटे का सौदा बन जाती है। कभी अत्यधिक उत्पादन से दाम गिर जाते हैं, तो कभी मौसम की मार पूरी फसल बर्बाद कर देती है। ऐसे समय में ग्रीनहाउस में टमाटर की खेती किसानों के लिए आशा की एक मजबूत किरण बनकर सामने आई है, जो उत्पादन, गुणवत्ता और आय तीनों में स्थिरता प्रदान करती है।

ग्रीनहाउस खेती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें प्रकृति पर निर्भरता कम हो जाती है। नियंत्रित तापमान और नमी के कारण टमाटर के पौधे स्वस्थ रहते हैं और लंबे समय तक फल देते हैं। पौधों पर लगने वाले फल आकार, रंग और गुणवत्ता में लगभग एक समान होते हैं, जिससे बाजार में उनकी मांग बढ़ जाती है। खुले खेतों में जहाँ टमाटर बारिश, पाले या तेज गर्मी से प्रभावित हो जाता है, वहीं ग्रीनहाउस में किसान इन जोखिमों से काफी हद तक सुरक्षित रहता है। आज के समय में उपभोक्ता न केवल सस्ती सब्जी, बल्कि सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन चाहता है।

ग्रीनहाउस में उगाए गए टमाटर कम रसायनों के उपयोग से तैयार होते हैं, जिससे वे स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर माने जाते हैं। यही कारण है कि शहरी बाजारों, बड़े खुदरा स्टोरों, होटलों और प्रोसेसिंग उद्योगों में ऐसे टमाटरों की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे किसानों को सीधे बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलने की संभावना भी बढ़ती है। ग्रीनहाउस टमाटर खेती से जल और उर्वरकों की बचत भी एक बड़ा लाभ है। ड्रिप सिंचाई और संतुलित पोषण प्रबंधन के कारण कम पानी में अधिक उत्पादन संभव होता है। वर्तमान समय में, जब जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, यह तकनीक टिकाऊ कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही, भूमि की उर्वरता भी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे भविष्य की खेती पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कई राज्यों में यह देखा गया है कि ग्रीनहाउस टमाटर अपनाने वाले किसान केवल स्थानीय मंडियों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि सीधे व्यापारियों, सुपरमार्केट और निर्यातकों से जुड़ रहे हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और किसान को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलता है। कुछ प्रगतिशील किसान चेरी टमाटर और रंगीन टमाटर जैसी विशेष किस्में उगाकर अतिरिक्त लाभ भी कमा रहे हैं। सरकारी नीतियाँ भी इस दिशा में सहायक साबित हो रही हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और अन्य योजनाओं के तहत ग्रीनहाउस निर्माण पर दी जाने वाली सब्सिडी ने छोटे और मध्यम किसानों के लिए इस तकनीक को सुलभ बनाया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। आज जब खेती को घाटे का व्यवसाय मानकर युवा वर्ग इससे दूर होता जा रहा है, ग्रीनहाउस टमाटर जैसी आधुनिक खेती पद्धतियाँ कृषि की छवि बदलने का कार्य कर रही हैं। यह तकनीक यह साबित करती है कि सही योजना, तकनीक और बाजार से जुड़ाव के साथ खेती भी एक सम्मानजनक और लाभदायक व्यवसाय बन सकती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि ग्रीनहाउस में टमाटर की खेती केवल एक नई कृषि तकनीक नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह किसानों को मौसम और बाजार की अनिश्चितताओं से बचाते हुए स्थायी आय प्रदान करती है। इस तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाया जाए, तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

आम में फल मक्खी एवं उसका नियंत्रण

● राम अवतार चौधरी ● आस्था
ramawatarmoond1999@gmail.com

आम भारत का प्रमुख फल है और इसकी गुणवत्ता एवं उत्पादन को कई कीट प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे खतरनाक कीट है। फ्रूट फ्लाई (फल मक्खी) यह मक्खी फल में अंडे देती है, जिससे फल सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और बाजार मूल्य कम हो जाता है। इसलिए फल मक्खी का प्रभावी नियंत्रण आम की सफल खेती के लिए आवश्यक है।

फल मक्खी क्या है?

● फल मक्खी एक छोटा भूरा-पीला रंग का कीट है।

● मादा मक्खी पके या कच्चे आम के फलों में छोटी-सी कट बनाकर अंडे देती है।

● कुछ दिनों बाद इन अंडों से लार्वा (कीड़े) निकलते हैं जो फल के गूदे को खा लेते हैं।

● परिणामस्वरूप फल सड़ने लगता है और पेड़ से गिर जाता है।

फल मक्खी से होने वाले नुकसान

● फलों में कीड़ा लगना

● उत्पादन में 30-80 प्रतिशत तक हानि

● फलों का समय से पहले गिरना

● बाजार में दाम कम मिलना

● निर्यात गुणवत्ता खराब होना

फल मक्खी के नियंत्रण के तरीके

स्वच्छता प्रबंधन

● गिरे हुए सड़े फलों को तुरंत इकट्ठा कर 'गड्ढे में दबाएँ' या नष्ट करें।

● संक्रमित फलों को पेड़ पर न छोड़ें।

● खेत साफ रखें, क्योंकि गिरे हुए फल मक्खी के प्रजनन का मुख्य स्रोत होते हैं।

बाइट ट्रैप

● प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट + कीटनाशक मिश्रण को ट्रैप में लगाएँ।

● यह वयस्क मक्खियों को आकर्षित कर उन्हें मार देता है।

● प्रत्येक एकड़ में 10-12 ट्रैप लगाने की सलाह दी जाती है।

मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप

● मिथाइल यूजेनॉल फल मक्खी के नर को आकर्षित करने वाला सबसे प्रभावी रसायन है।

● 1 लीटर पानी में मिथाइल यूजेनॉल + मैलाथियान मिलाकर लकड़ी के टुकड़ों पर डालें।

● इन्हें पेड़ों पर टांग दें।

● यह तकनीक नर मक्खियों की संख्या कम करती है, जिससे प्रजनन घटता है।

बैगिंग तकनीक

● कच्चे आमों पर पेपर/नेट बैग लगाएँ।

● इससे मक्खियाँ फलों तक नहीं पहुँच पातीं।

● यह तकनीक पूरी तरह जैविक और अत्यंत प्रभावी है।

जैविक नियंत्रण

● नीम तेल का छिड़काव 3-4 बार करें।

● फलों पर नीम खली घोल, लाल मिर्च+नीम मिश्रण का भी प्रयोग किया जा सकता है।

● स्पिनोसैड जैसे जैविक कीटनाशक सुरक्षित विकल्प हैं।

रासायनिक नियंत्रण

● छिड़काव तभी करें जब संक्रमण अधिक हो और आम पर बैगिंग न की गई हो।

● कीटनाशक का प्रयोग फूल आने और फल बनने के बाद सावधानी से करें।

● छिड़काव कटाई से 20-25 दिन पहले बंद कर देना चाहिए।

निवारक उपाय

● समय-समय पर बाग का निरीक्षण करें।

● पकने के शुरुआती समय में ही ट्रैप लगा दें।

● सिंचाई और पोषण संतुलित रखें ताकि पेड़ स्वस्थ रहे।

● पेड़ की छंटाई सही समय पर करें।

निष्कर्ष

आम में फल मक्खी एक गंभीर कीट है, परंतु सही प्रबंधन और समय पर नियंत्रण से इसकी हानि को काफी कम किया जा सकता है। स्वच्छता, ट्रैप, बैगिंग और जैविक तरीकों का संयोजन अपनाकर किसान उच्च गुणवत्ता के आम प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में बेहतर भाव पा सकते हैं।

मधुमक्खी की शत्रु ट्रोपिलेप्स, एकरापिस वुडी माईट एवं प्रबंधन

● डॉ. अभिषेक शुक्ला
कीट विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय
नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, वघई, गुजरात

ट्रॉपिलेप्स माईट एक परजीवी माईट है जो मुख्य रूप से मधुमक्खी शिशुओं और वयस्कों को प्रभावित करती है। यह मुख्य रूप से एशियाई क्षेत्रों में पायी जाती है, लेकिन मधुमक्खी पालन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है और मधुमक्खियों के परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती है। ट्रोपिलेप्स माइट (ट्रोपिलेप्स क्लारी और ट्रोपिलेप्स मर्सिडेसी) की दो प्रजातियां यूरोपीय मधु मक्खियों (एपिस मेलिफेरा) पर परजीवीकरण करती पायी गयी हैं। यह माईट एक बाह्य-परजीवी (एक्टो-पैरासिटिक) माईट है जो नर और श्रमिक मधुमक्खियों के प्यूपा के रक्त (हिमोलिम्फ) को चूसती है, साथ ही ये ब्रूड पर भी प्रजनन करती है।

पहचान: ये माईट लाल-भूरे रंग की, लगभग 1.0 मि.मी. आकार की तथा 0.5 मि.मी. चौडी, अति सक्रिय माईट है। ये माईट, प्राय: वरोआ माईट के आकार से लगभग एक तिहाई ही होती है। इनके शिशु चार जोड़ी पैर वाले होते हैं तथा इनके पैरों की पहली जोड़ी प्राय: श्रृंगिका की तरह सीधी होती है और इनका शरीर खंडित होता है। यह माईट तेजी से चलती है, जिसे छत्ते के निरीक्षण के दौरान आसानी से देखा भी जा सकता है। ब्रूड कोशिकाओं में पाए जाने वाले युवा शिशु तथा प्यूपा सफेद रंग के होते हैं और मधुमक्खी के शिशुओं का भक्षण करते समय आमतौर पर ये गतिहीन हो जाती हैं।

जीवन चक्र और प्रजनन: ट्रॉपिलेप्स माईट का जीवन चक्र कई मायनों में वरोआ माईट के समान ही होता है, क्योंकि दोनों माईट प्रजातियाँ बाह्य-परजीवी है जो मधुमक्खी के प्रारंभिक चरणों को परजीवी बनाती हैं। हालाँकि, वरोआ माईट की तुलना में इसकी प्रजनन दर अधिक होने के कारण इस माईट का जीवन-चक्र बहुत छोटा होता है। मादा ट्रॉपिलेप्स माईट, ब्रूड कोशिकाओं में अंडे देती हैं। ट्रॉपिलेप्स माईट अपना जीवन चक्र 7 से10 दिनों में पूरा करता है, जिससे इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है।

मधुमक्खियों पर प्रभाव: ट्रॉपिलैप्स माईट के संक्रमण से मधुमक्खी कालोनियों को गंभीर नुकसान होता है

विकृति: विकासशील मधुमक्खियों में शारीरिक असामान्यताएं जैसे विकृत छत्ते और वयस्क मधुमक्खियों में नाटापन, क्षतिग्रस्त पंख, पैर तथा पेट आदि दिखना सामान्य है इससे परजीवी माईट सिंड्रोम और कॉलोनी में गिरावट (कोलेप्स) आदि देखे जाते हैं।

ब्रूड का विनाश: ट्रॉपिलैप्स माईट के संक्रमण से मधुमक्खी कालोनियों की ब्रूड कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं।

कमज़ोर कॉलोनी: ट्रॉपिलैप्स माईट के संक्रमण से मधुमक्खी कॉलोनी कमजोर हो जाती है और उत्पादकता कम हो जाती है। यहां से मधुमक्खी कॉलोनी छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगती है और ये इस माईट को नए स्थानों पर तेज़ी से फैलाती भी है। ये माईट वायरस को भी फैलाती हैं जो कॉलोनी के स्वास्थ्य और रोग की संवेदनशीलता को बहुत अधिक प्रभावित करती है।

नियंत्रण के उपाय

निगरानी: ब्रूड सेल की नियमित निगरानी करने से इसकी सही समय पर पहचान की जा सकती है।

जैविक उपायों से: माईट-प्रतिरोधी मधुमक्खियों का चयन करके भी इसका प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है।

रासायनिक उपचार: प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक एसिड और एसेंशियल तेलों का समय आने पर इस माईट के नियंत्रित हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

श्वांस नाली की माईट (एकरापिस वुडी)

श्वांस नाली की माईट, एक्रेपिस वुडी एक अति सूक्ष्म माईट है जो मधुमक्खियों की श्वसन तंत्र को संक्रमित करती है। यह मधुमक्खी की उड़ान और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। एक्रेपिस वुडी मधुमक्खियों के श्वसन तंत्र की एक सूक्ष्म, आंतरिक माईट है, जो रानी मधुमक्खियों, ड्रोन और श्रमिक मधुमक्खियों को संक्रमित करती है।

ये माईट, मधुमक्खियों के श्वसन पथ को अंदर से संक्रमित करती है और वही पर प्रजनन करती है और मधुमक्खी के रक्त (हेमोलिम्फ) को चूस कर अपना जीवन निर्वाह करती है। ये संक्रमित मधुमक्खी की सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। ये माईट विभिन्न रोगज़नकों के लिए श्वासनली की सतह को खोल देती है और पंख की मांसपेशियों में वायु प्रवाह को कम कर देती है। इसके परिणामस्वरूप मधुमक्खियाँ कमजोर और बीमार हो जाती हैं और उनका जीवनकाल काफी कम हो जाता है।

जीवन चक्र और प्रजनन: इस माईट का पूरा जीवन चक्र एक संक्षिप्त प्रवास अवधि को छोड़कर मधुमक्खी के श्वासनली के अंदर ही पूरा होता है। श्रमिक मधुमक्खियाँ अपनी कोशिकाओं से बाहर आने के 24 घंटों के भीतर मादा माईट, वयस्क मधुमक्खियों की श्वासनली में प्रवास करती है और जीवन भर या जब तक उनकी मेजबान मधुमक्खी मर नहीं जाती तब तक वहीं रहती है। एक बार में मेजबान मधुमक्खी के अंदर, प्रत्येक मादा माईट 3 से 4 दिनों की अवधि में 5 से 7 अंडे देती है और जीवन भर अंडे देती रहती है। अंडे 3 से 4 दिनों में फूटते हैं और लार्वा अवस्था से गुजरती हैं, फिर वयस्क चरण तक पहुँचने से पहले भिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। नर को पूरी तरह विकसित होने में 11 से 12 दिन लगते हैं, जबकि मादाओं को 14 से 15 दिन लगते हैं।

मधुमक्खियों पर प्रभाव: ये माईट आकार में अतिसूक्ष्म होती है और इसलिए सामान्यतया नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। संक्रमण के कोई विश्वसनीय अथवा दिखाई देने वाले कोई लक्षण नहीं होते हैं, जिससे इसका पता लगाना अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है। एक सामान्य वक्ष पर पायी जाने वाली श्वासनली स्पष्ट, रंगहीन या हल्के क्रीम-पीले रंग की होती है। इसके विपरीत, संक्रमित श्वासनली का रंग फीका पड़ जाता है और माईट ग्रसन के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे खराब हो जाती है। गंभीर रूप से संक्रमित मधुमक्खियों की श्वासनली भूरे धब्बों और पपड़ी जैसे घावों के साथ काली दिखाई देती है। इस माईट से ग्रसित मधुमक्खियों के पंख कमजोर हो जाते है जिससे प्रभावित मधुमक्खियाँ ठीक से उड़ नहीं पातीं हैं और पंखों को विषम कोण से पकड़ना एक सामान्य विशेषता है।

नियंत्रण के उपाय

निगरानी: श्वासनली संक्रमण की जांच के लिए विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है।

रासायनिक उपचार: फॉर्मिक एसिड या अन्य लक्षित समाधानों का उपयोग किया जाता है।

जैविक विधियाँ: मधुमक्खी कालोनियों की प्राकृतिक प्रतिरक्षा को मजबूत करना एक बहुत अच्छी विधि है।

कृषक जगत राष्ट्रीय कृषि अखबार भोपाल-जयपुर-रायपुर द्वारा प्रकाशित फसल पुस्तक श्रृंखला

नाम ..... ग्राम.....
पोस्ट ..... तह. ..... जिला.....
फोन/मोबा. ..... कुल राशि.....
ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या/संलग्न ड्रॉफ्ट नं. .....
मनी ऑर्डर क्र. ..... वी.पी. भेजें।

नोट : कृपया ड्राफ्ट या मनीऑर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम नीचे लिखे पते पर भेजें

प्रधान कार्यालय : 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011
फोन: 0755-4248100,2554864, मो. : 9826255861
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर
मो. : 09826021837

समस्या -समाधान

समस्या – पपीता अक्टूबर में लगाया था जैविक खाद का उपयोग किया था पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है और पत्तियों में पीलापन आ रहा है उपाय बतलाये।

– तुलाराम नरवरिया

समाधान– आप केवल जैविक उत्पादन का प्रयोग करके खेती करते हैं यह बात अनुकरणीय है। जहां तक बढ़वार का प्रश्न है गिरते तापमान का तो असर होगा ही। पौधों का रखरखाव भी करना पड़ता है। आप निम्न उपचार करें।

- अच्छी पकी हुई गोबर खाद 10 किलो/ पौध पौधों के चारों ओर सक्रिय जड़ों के पास थाला बना कर बिखेरें।
- पत्तियों पर पीलापन खतरनाक लक्षण है यह कहीं वाईरस का आक्रमण तो नहीं है वाईरस पौधों में सफेद मक्खी के कारण आता है। सफेद मक्खी की सक्रियता पर नजर रखें अन्यथा बीमारी बढ़ जायेगी।
- जैविक कीटनाशक स्वयं बनाकर उपयोग करें 1 किलो तम्बाकू के पत्ते, 500 ग्राम नीम का तेल, 25 ग्राम कपड़े धोने का साबुन। तंबाकू के पत्तों को 5 लीटर पानी में 3 दिन तक भिगोकर रखें, निचोड़ कर घोल में 500 ग्राम नीम तेल डालें तथा 25 ग्राम साबुन मिलायें। 500 लीटर पानी में 15 लीटर घोल बनाकर छिड़काव करें।

समस्या– मैं जायद की तिल लगाना चाहता हूं क्या मुझे आर्थिक लाभ अन्य फसलों की तुलना में अधिक होगा तकनीकी बतायें।

– जयशंकर लाल

समाधान – जायद के मौसम में मक्का, तिल, मूंगफली, भिंडी, मूंग, उड़द लगाकर अतिरिक्त आय कमाई जा सकती हैं। तिल्ली की काश्त अगर निम्न तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखकर की जाये तो खरीफ की तुलना में जायद में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। आपको पता होगा बाजार में फुटकर भाव में तिल्ली 200 किलो तक बिक रही है यदि 700–800 किलो/हे. भी पैदा कर ली जाये तो अच्छी आय संभव है।

- तिल्ली की विकसित जातियाँ जैसे टी.के.जी.22, टी.के.जी.55, जे.टी.एस. 8, टी.के.जी. 36 इत्यादि प्रमुख हैं।
- बुआई का उचित समय फरवरी माह है जब तक केवल आलू, मटर, तोरिया इत्यादि के खेत उपलब्ध हो सकेंगे।
- उर्वरक में नत्रजन (यूरिया) 130 किलो, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश 33 किलो/हे. दिया जाये।
- उर्वरक बीज मिश्रण कदापि नहीं किया जाये।
- बीज दर 5–6 किलो/हे. यथासंभव खेत में कतार खाली बनाकर गोबर की खाद में बीज मिलाकर हाथ से ऊरा जाये तो अच्छा अंकुरण मिल सकेगा।
- पत्तीमोडक कीट तथा भभूतिया रोग के नियंत्रण के लिये क्विनालफॉस 25 ई.सी. 2 मि.ली./लीटर पानी में घोल बनाकर दो छिड़काव 15 दिनों के अंतर से तथा भभूतिया की रोकथाम के लिये सल्फेक्स 2 ग्राम/लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से दो छिड़काव करें।

समस्या – मेरी लहसुन की फसल पर पत्तियां पीली पड़ रही हैं उपाय बतायें।

– पप्पूनाथ बैरागी

समाधान – किसी भी फसल के पीलापन के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। आपकी फसल में माहो का प्रकोप, पत्तियों पर धब्बा रोग, पानी की अधिकता अथवा नत्रजन उर्वरक की कमी कोई भी कारण हो सकता है। जिसके चलते फसल में पीलापन/पत्तियां सूखने के लक्षण आ रहे हैं। आप निम्न उपाय करें–

- यदि पर्याप्त उर्वरक पूर्व में नहीं दिया गया हो तो यूरिया फसल में सिंचाई/निंदाई के बाद दें।
- यदि जल लग्नता की स्थिति दिखाई दे रही हो अतिरिक्त जल का रिसाव करें।
- डाईथेन एम 45 की दो ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से दो छिड़काव करें।
- रोगर 1 मि.ली./लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से दो छिड़काव करें।

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान

कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) फोन-0755-4248100,2554864

प्राकृतिक खेती – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

खरपतवार प्रबंधन

प्राकृतिक खेती में खरपतवार प्रबंधन करने के असरदार तरीके क्या हैं?

असरदार खरपतवार प्रबंधन तरीकों में पलवार, हाथ से खरपतवार निकालना और नीम आधारित उत्पाद जैसे प्राकृतिक खरपतवारनाशकों का इस्तेमाल करना शामिल है।

क्या पलवार प्राकृतिक खेती में खरपतवार प्रबंधन में मदद कर सकती है, और यह कैसे किया जाता है?

हाँ, पलवार या (मल्चिंग) में खरपतवार को बढ़ने से रोकने और नमी बचाने के लिए मिट्टी को पुआल, पत्तियों या फसल के बचे हुए हिस्सों जैसी जैविक सामग्री से ढका जाता है।

क्या कोई प्राकृतिक खरपतवारनाशक या खरपतवार हैं जिनका मैं प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल कर सकता हूँ?

नीम-आधारित उत्पाद और विनेगर सॉल्यूशन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना प्राकृतिक खरपतवार दमन के तौर पर काम कर सकते हैं।

कटाई और कटाई के बाद के तरीके

प्राकृतिक खेती में मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी फसल कटाई के लिए तैयार है?

आपकी फसल कटाई के लिए तैयार है या नहीं, यह जानने के लिए रंग परिवर्तन, पत्तों का सूखना, फल/अनाज की बनावट (कठोरता/नमी), और फसल की नमी के स्तर जैसे प्राकृतिक संकेतों पर ध्यान दें।

प्राकृतिक खेती में फसलों की कटाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सबसे अच्छे तरीके क्या हैं?

तेज़, साफ़ औज़ारों का इस्तेमाल करें, फसलों को धीरे से संभालें, और खराब मौसम में कटाई से बचें।

क्या कटी हुई उपज की भंडारण अवधि बढ़ाने के लिए कोई प्राकृतिक तरीके हैं?

स्वच्छ भंडारण, ठंडा तापमान और प्राकृतिक परिरक्षकों का उपयोग करने जैसी तकनीकें कटी हुई उपज की भंडारण अवधि बढ़ा सकती हैं।

जैविक उपज को खराब होने और कीटों से बचाने के लिए मुझे इसे कैसे भण्डारण करना चाहिए?

उत्पाद को साफ, हवादार कंटेनर या कमरों में स्टोर करें, और कीटों को रोकने के लिए नीम के पत्तों जैसे प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करने पर विचार करें।

कृषक जगत बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक रु. 95 कोड : 016
सब्जियों में पौध संरक्षण रु. 75 कोड : 017
मशरूम एक लाभ अनेक रु. 45 कोड : 019
मिर्च की उन्नत खेती रु. 55 कोड : 020
केला उत्पादन रु. 70 कोड : 025
गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण रु. 75 कोड : 027
पपीता रु. 55 कोड : 031
अदरक रु. 55 कोड : 032
फलों की खेती रु. 75 कोड : 040
सजाएं फूलों से बगिया रु. 65 कोड : 041
घर की बगिया रु. 95 कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम _____
ग्राम _____ पोस्ट _____ तह. _____
जिला _____ फोन/मोबा. _____
कुल राशि _____ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या _____
संलग्न ड्राफ्ट नं. _____ मनी आर्डर रसीद क्र. _____ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

आंवला स्वास्थ्य लाभ एवं मूल्य वर्धित उत्पाद - 2

आंवला के उत्पाद

● निधि जोशी
joshinidhi894@gmail.com

आंवला एक अत्यंत पोषक और औषधीय गुणों से भरपूर फल है, जिसे आयुर्वेद में 'अमृत फल' की संज्ञा दी गई है। यह छोटा, हरा-पीला फल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले यौगिकों से भरपूर है और भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान में गहराई से निहित है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज तत्व और फाइबर पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पाचन सुधारने, त्वचा व बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा मधुमेह व हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक होते हैं। आंवले का नियमित सेवन समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आंवले से विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार किये जाते हैं, जो न केवल इसके पोषण गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखतें हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण साधन बनतें हैं।

आंवले का विभिन्न प्रकार के मूल्य वर्धित उत्पादों में उपयोग किया है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसकी बाजार में मांग का विस्तार करता है।

आंवला जूस- ताजा आंवला का रस एक लोकप्रिय उत्पाद है जो अपने तीखे स्वाद और केंद्रित स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। प्रतिरक्षा में सुधार और शरीर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए इसका सेवन स्वास्थ्य टॉनिक के रूप में किया जाता है।आंवला जूस बनाने के लिए ताजे व पके आंवले धोकर बीज निकालें और छोटे टुकड़ों में काट लें। इन टुकड़ों को थोड़े पानी के साथ मिक्सर में पीसकर छलनी से छान लें। स्वादानुसार काला नमक या शहद मिलाकर आंवला जूस सेवन कर सकते हैं।

आंवला मुरब्बा- आंवला मुरब्बा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट परिरक्षित उत्पाद है, जिसे आंवले के टुकड़ों को चाशनी में पकाकर तैयार किया जाता है। इसकी प्रक्रिया में आंवले उबालकर बीज निकालते हैं, फिर चीनी की चाशनी में हल्की आंच पर पकाते हैं।अंत में इलायची या केसर मिलाकर ठंडा कर भंडारण किया जाता है, जिससे यह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।

आंवला पाउडर- सूखे आंवला को पीसकर एक महीन पाउडर बनाया जाता है, जिसका उपयोग हर्बल चाय, सप्लीमेंट्स और स्किनकेयर उत्पादों में किया जाता है।

कैंडिड आंवला- कैंडीड आँवला एक पौष्टिक व स्वादिष्ट मूल्यवर्धित उत्पाद है, जिसे ताजे आँवले से सरल विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी प्रक्रिया में आँवले को धोकर उबालना, बीज निकालना तथा चीनी की चाशनी में कुछ समय तक भिगोकर सुखाना शामिल है। यह उत्पाद विटामिनसी से भरपूर होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और स्वरोज़गार व आय-वृद्धि के लिए उपयोगी है।

आंवला अचार- आँवले का अचार बनाने के लिए ताजे आँवले धोकर उबाल या भाप में नरम किए जाते हैं, फिर उनके टुकड़े कर बीज निकाल दिए जाते हैं। इन टुकड़ों को नमक, हल्दी, सौंफ, मेथी, सरसों और लाल मिर्च पाउडर जैसे मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाया जाता है। सरसों का तेल मिलाकर अचार को काँच के जार में भरकर कुछ दिनों तक धूप में रखा जाता है, जिससे स्वाद विकसित होता है। आँवले का अचार आहार में आंवला के उपयोग में विविधता जोड़ता है।

आंवला जैम और चटनी- आँवला जैम और चटनी बनाने के लिए ताज़े आँवले को धोकर उबाल या भाप में पकाया जाता है, फिर बीज निकालकर गूदा तैयार किया जाता है। जैम के लिए गूदे में चीनी मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाया जाता है, जबकि चटनी के लिए इसमें नमक, मसाले और सिरका/नींबू रस मिलाया जाता है। ये दोनों उत्पाद स्वादिष्ट होने के साथ पोषण से भरपूर हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

हर्बल सप्लीमेंट और कैप्सूल- आंवला हर्बल सप्लीमेंट एवं कैप्सूल प्राकृतिक रूप से विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करने, त्वचा और स्वास्थ्य बनाए रखने में उपयोगी माने जाते हैं।

स्किनकेयर उत्पाद- आंवला अपनी त्वचा और बालों को बढ़ाने वाले गुणों के कारण शैंपू, तेल और फेस मास्क में एक प्रमुख घटक है। यह सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

किण्वित उत्पाद- आंवला-आधारित वाइन, साइडर और प्रोबायोटिक्स नवीन उत्पादों के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, जो फल के प्राकृतिक किण्वन गुणों का लाभ उठाते हैं।

स्वास्थ्यवर्धक है खीरा

खीरा स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद रहता है। खीरे के सेवन से पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसका प्रयोग होटल, ढाबे तथा शहरों में अधिकतर खाना खाने के साथ सलाद के रुप में करते है। खीरे के सेवन करने से मनुष्य के शरीर को पानी की पूर्ति होती है। इसके प्रयोग से पोषक तत्वों की भी पूर्ति होती है। इस प्रकार से खीरे के अंदर निम्न पोषक तत्व होते हैं, जैसे- पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, खनिज पदार्थ, कैलोरीज, फॉस्फोरस, विटामिन सी तथा अन्य कार्बोहाइड्रेटस। बाजार में खीरे की अधिक मांग बने रहने के कारण खीरे की खेती किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। खीरे का उपयोग खाने के साथ सलाद के रुप में बढ़ता ही जा रहा है, जिससे बाजार में इसकी भी कीमते लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही खीरे की खेती रेतीली भूमि में अच्छी होती है। गर्मियां आते ही खीरा हर घर की एक जरुरत बन जाता है। शरीर को ठंडक देने के लिए ये एक कारगार और नेचुरल उपाय है। मुख्य रुप से सलाद में प्रयोग होने वाले खीरे में बहुत कम मात्रा में कैलोरी पायी जाती है। यही वजह है कि यह मोटापा कम करने के इच्छुक लोगों के लिए

किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे सिर्फखीरा ही नहीं इसका छिलका भी बहुत उपयोगी है। खीरे के छिलके से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

पाचन के लिए फायदेमंद: खीरे के छिलके में ऐसे फाइबर मौजूद होते हैं जो घुलते नहीं है, ये फाइबर पेट के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। कब्ज की परेशानी को दूर करने में भी ये कारगर है, तथा पेट भी अच्छी तरह साफ हो जाता है।

वजन कम करने में सहायक: खीरे भी वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छिलके के साथ इसका सेवन करना और भी अधिक फायदेमंद रहता है।

विटामिन-के का अच्छा माध्यम: खीरे के छिलके में विटामिन-के पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ये विटामिन प्रोटीन को एक्टिव करने का काम करता है। जिसकी वजह से कोशिकाओं के विकास में मदद मिलती है, साथ ही इससे ब्लड-क्लॉटिंग की समस्या भी पनपती है।

आंखों के लिए: छिलके समेत खीरा खाने से आंख की रोशनी अच्छी रहती है। इसके छिलके में बीटा कैरोटीन होता है, जिससे आंखों की रोशनी अच्छी होती है।

त्वचा के लिए: टैनिंग और सनबर्न में भी खीरे के छिलके का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। इससे त्वचा का रुखापन भी कम होता है और मॉश्चराइजर बना रहता है। कई लोग इसके छिलके को सुखाकर पीस लेते हैं और उसमें गुलाब जल की बूंदें मिलाकर फेस पैक की तरह इस्तेमाल करते हैं।

सर्दियों का टॉनिक चुकंदर सेहत के लिए लाभदायक

शायद कम लोग ही जानते हैं कि चुकंदर में लौह तत्व की मात्रा अधिक नहीं होती है, किंतु इससे प्राप्त होने वाला लौह तत्व उच्च गुणवत्ता का होता है, जो रक्त निर्माण के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चुकंदर का सेवन शरीर से अनेक हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में बेहद लाभदायी है।

चुकंदर के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इसके कंद के अलावा चुकंदर की हरी पत्तियों का सेवन भी बेहद लाभदायी है। इन पत्तियों में कंद की तुलना में तीन गुना लौह तत्व अधिक होता है। पत्तियों में विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कंद व इसकी पत्तियां रक्त निर्माण के लिए व हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने अर्थात् क्लींजर के रूप में कार्य करते हैं। चुकंदर में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज व रेशे की पर्याप्त मात्रा होती है। पाचन योग्य शर्करा की उपस्थिति के कारण चुकंदर का सेवन ऊर्जा भी प्रदान करता है। ऐसा समझा जाता है कि चुकंदर का गहरा लाल रंग इसमें लौह तत्व की प्रचुरता के कारण है, बल्कि सच यह है कि चुकंदर का गहरा लाल रंग इसमें पाए जाने वाले एक रंगकण (बीटा सायनिन) के कारण होता है। एंटी ऑक्सीडेंट गुणों के कारण ये रंगकण स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं।

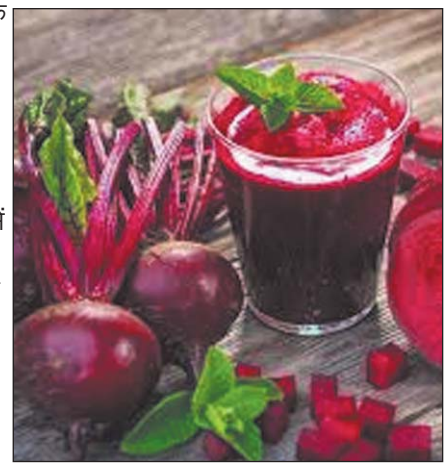

चुकंदर में पाए जाने वाले फोलिक एसिड, पोटेशियम व मुलायम रेशा भी इसके पोषणिक गुणों को बढ़ाते हैं। चुकंदर का नियमित सेवन संपूर्ण शरीर को निरोग रखने में सहायक है। हालांकि हमारे दैनिक आहार में चुकंदर को अभी भी उचित स्थान प्राप्त नहीं है, फिर भी इसे नियमित खाने से ना सिर्फ कई रोगों में लाभ होता है बल्कि यह त्वचा की खूबसूरती भी प्रदान करता है। इससे हिमोग्लोबिन बढ़ता है फलस्वरूप चेहरे की लालिमा बढ़ती है।

पाक्षिक पंचांग

19 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक
विक्रम संवत् 2082
माघ शुक्ल 1 से माघ शुक्ल 15 तक

दि.	माह	वार		तिथि	त्यौहार
19	जनवरी	सोम	माघ शुक्ल	1	
20	जनवरी	मंगल	----------	2	पंचक 1.48 रात से
21	जनवरी	बुध	----------	3	पंचक
22	जनवरी	गुरु	----------	4	विनायकी चतुर्थी व्रत, पंचक
23	जनवरी	शुक्र	----------	5	बसंत पंचमी, पंचक
24	जनवरी	शनि	----------	6	शीतलाष्टमी व्रत, पंचक
25	जनवरी	रवि	----------	7	नर्मदा जयंती, पंचक 12.7 दिन तक
26	जनवरी	सोम	----------	8	गणतंत्र दिवस
27	जनवरी	मंगल	----------	9	महानंदा नवमी
28	जनवरी	बुध	----------	10	
29	जनवरी	गुरु	----------	11	जया/अजा एकादशी व्रत
30	जनवरी	शुक्र	----------	12	प्रदोष व्रत
31	जनवरी	शनि	----------	13/14	
1	फरवरी	रवि	----------	15	माघी पूर्णिमा/स्ना.दा. पूर्णिमा

कृषि विभाग ने जारी की कीटों के रोकथाम के लिए एडवाइजरी

सरसों की फसल में माहू एवं चेपा (एफिड) से बचाव के लिए करें उपाय

अजमेर। मौसम की अनुकूलता के साथ क्षेत्र में कीट रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना के मध्य नजर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री संजय तनेजा ने अधिकारियों को फसलों पर निगरानी रखने और उप जिला अजमेर और केकड़ी को ग्राउंड लेवल पर फील्ड सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए।

कृषि अधिकारी श्री पुष्पेंद्र सिंह ने किसानों को माहू (चेपा) से बचाव के उपाय करने के लिए कहा। इसके रोकथाम और नियंत्रण के सुझाव दिए। वर्तमान मौसम परिस्थिति में सरसों की फसल में माहू (एफिड) कीट होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसका यदि समय रहते उपचार नहीं किया जाए तो इस रोग की रोकथाम का कार्य काफी दुष्कर एवं खर्चीला या असंभव हो जाता है। इससे फसल के उत्पाद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है तथा किसानों को कृषि उत्पाद का बाजार भाव भी कम मिलता है।

कीट की पहचान- यह कीट छोटे से माध्यम गोल आकार का होता है और पीले हरे या जैतून रंग का होता है और इसमें कर्निकल्स (माँ स्त्रावित करने वाली नालियाँ) की एक जोड़ी होती है। शरीर हल्के सफेद पाउडर से ढ़का होता है। इसकी लम्बाई लगभग 1.4 से 2.4 मिलीमीटर होती है।

कीट के लक्षण- अधिक प्रकोप के कारण पतियों का मुड़ना, पीला पड़ना एवं सूखना जैसे लक्षण दिखाई देते है। ये चीनी युक्त चिपचिपा तरल (हनीड्यू) पदार्थ स्त्रावित करता है जो कालिख सांचे के विकास के लिए जिम्मेदार होता है जो पोधे में प्रकाश संश्लेषण दर को कम करता है।

किसान सरसों की फसल में माहू एवं चेपा अथवा एफिड की रोकथाम के लिए उपाय अपना कर संभावित नुकसान से फसल को बचा सकते है। क्रिसोपरला का 50000 प्रति हेक्टर के हिसाब से 10 दिवस के अन्तराल पर दो बार भुरकाव करावे। मित्र फफूंद वर्टिसीलीयम लेकानी 5 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी के साथ मिलकर छिड़काव करावे। कीट का प्रकोप होने पर नीम आधारित कीटनाशक एजाडीरेक्टिन 0.03 ईसी का 2 लीटर प्रति हैक्टर छिडकाव करावे। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर विभागीय सिफारिश अनुसार किट नाशी रसायनों का सुबह या शाम के समय कॉन्टेक्ट एवं सिस्टमिक श्रेणी के रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग कृषि विभाग की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों द्वारा तकनीकी सिफारिशानुसार करे।

अधिक जानकारी के लिए किसान स्थानीय कृषि पर्येवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी या नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर परामर्श उपरांत प्रभावी उपाय अपनाकर कीट-व्याधियों की रोकथाम सम्बंधित कार्य करावे।

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-

- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि
- बीज ▪ औषधीय फसल

विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक

- अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.

कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेवल्स, तीर्थ यात्रायें, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
(सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक)
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagat
@krishakjagatindia @krishak_jagat

जीरे में झुलसा रोग प्रबंधन

अजमेर। रबी की फसल जीरे में होने वाले झुलसा रोग से बचाव के लिए किसानों को विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए।

ग्राह्य परीक्षण केन्द्र, तबीजी फार्म के कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि) डॉ. जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि बीजीय मसाला फसलों में जीरा एक महत्वपूर्ण फसल हैं। जीरे का उपयोग सभी सब्जियों, सूप, आचार, सॉस आदि को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता हैं। जीरे की फसल में कई हानिकारक रोगों का प्रकोप होता हैं। इनमें से झुलसा रोग का समय पर नियंत्रण नहीं करने पर काफी हानि होती हैं। इसलिए कृषकों को सलाह दी जाती हैं कि जीरे की फसल को रोगों से बचाने हेतु विभागीय सिफारिश अनुसार फफूंद नाशियों का छिड़काव करें तथा छिड़काव करते समय हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क तथा पूरे वस्त्र पहने।

उन्होंने बताया कि झुलसा

रोग एक कवक जनित रोग हैं इसको सामान्य भाषा में इसको काल्या रोग के नाम से भी जाना जाता हैं। फसल में फूल आने वाली अवस्था में अगर आकाश में बादल छाये रहे तो इस रोग का प्रकोप होने की संभावना बढ जाती है। रोग के प्रकोप से पौधों की पत्तियों के सिरे झुके हुए नजर आते हैं। पौधों की पत्तियां व तनों पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। यह रोग पत्तियों से वृन्त, तने एवं बीजों पर फैल जाता हैं। इस रोग का प्रसार इतना तीव्र होता हैं कि अगर समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो फसल को बचाना मुश्किल हो जाता हैं।

उन्होंने बताया कि इस रोग से बचाव हेतु बुवाई के 30-35 दिन बाद दो ग्राम थायोफेनेट मिथाइल प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा आवश्यकतानुसार 15 दिन बाद दोहराएं अथवा रोग के लक्षण दिखाई देने पर डाईफेनोकोनाजॉल का 0.5 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें तथा दुसरा व तीसरा छिड़काव 15 दिन के अन्तराल पर पुन: दोहराएं अथवा बुवाई के 35 दिन बाद एक मिली लीटर प्रोपीकोनाजोल का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आवश्यकतानुसार 15 दिन के अन्तराल पर तीन छिड़काव करें।

खरीफ फसल खराबा से प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत

जयपुर। जयपुर जिला कलक्टर, द्वारा गत खरीफ फसल की करवाई गई नियमित गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर फुलेरा तहसील के गांव शार्दूलपुरा गांव को अभावग्रस्त घोषित किया है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की शासन उपसचिव श्रीमती शैफाली कुशवाहा ने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से शार्दूलपुरा में कृषकों की फसल में बाढ़ से 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के कारण शार्दूलपुरा गांव को अभावग्रस्त घोषित किया है। प्रभावित कृषकों को केन्द्र सरकार के एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान वितरण की अनुमति दी गई है। ये प्रावधान प्रभावित गांव में इस अधिसूचना के जारी होने से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगे।

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
⇨ वार्षिक रु. 600/- ⇨ दो वर्ष रु. 1000/-
⇨ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम .....पो. .....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

सहकार संगम- 2026 कार्यक्रम का आयोजन

सहकारी समितियों को आर्थिक सशक्त एवं लाभांश देने लायक बनाने की आवश्यकता : श्री दक

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि निरीक्षक सहकारिता विभाग की रीढ़ हैं, वे अपनी भूमिका को और विस्तार देते हुए सहकारी समितियों के संरक्षक और मार्गदर्शक बनें। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सहकारी समितियों को वर्तमान समय के अनुरूप सशक्त, सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी बनाना होगा।

श्री दक जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एसोसिएशन ऑफ राजस्थान को-ऑपरेटिव सबोर्डिनेट सर्विसेज द्वारा आयोजित 'सहकार संगम-2026' कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विशेष रूप से रोजगार सृजन में सहकारिता क्षेत्र बड़ी भूमिका निभा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री की इस मंशा को साकार करने के लिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करना होगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि आर्थिक युग का प्रभाव विगत वर्षों में सहकारी संस्थाओं पर पड़ा, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गई। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री माननीय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना के अनुरूप एवं केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 120 पहलों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। सहकारी समितियों के माध्यम से अब पेट्रोल पम्प तक का संचालन किया जा सकता है। राज्य में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सहकारी सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसे में हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सहकारी समितियों को आर्थिक सशक्त और लाभांश देने लायक बनाएं। श्री दक ने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितताओं की रोकथाम के लिए सहकारी निरीक्षक निरन्तर सजग रहते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग करें। कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ राजस्थान को-ऑपरेटिव सबोर्डिनेट सर्विसेज की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा चौधरी ने कहा कि राज्य में 600 से अधिक सहकारी निरीक्षक अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप सहकारिता को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकार संगम कार्यक्रम इस वृहद् परिवार के लिए संवाद का एक मंच है, जिसके माध्यम से वे अपनी आपसी समझ को बढ़ाते हुए और एक-दूसरे के अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे।

प्रारम्भ में सहकारिता मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारम्भ किया। उन्होंने राजकीय सेवा से इतर सामाजिक सरोकार निभाने वाले निरीक्षकों को सहकार रत्न पुरस्कार प्रदान किए।

सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारीगण, सहकार भारती के पदाधिकारी एवं प्रदेश भर से आए सहकारी अधिकारी व निरीक्षक कार्यक्रम में मौजूद रहे।

कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं को मिलेगी 15 से 40 हजार तक छात्रवृत्ति

बीकानेर। कृषि संकाय लेने वाली बेटियों को कृषि विभाग छात्रवृत्ति दे रहा है। इसी का परिणाम रहा कि छात्राओं का रुझान कृषि संकाय की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक मदनलाल ने बताया कि विगत सालों में कृषि संकाय में अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है। बड़ी संख्या में छात्राएं कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी व खाद्य प्रसंस्करण जैसे अध्ययन के नए क्षेत्रों में उतर रही हैं।

सहायक निदेशक उद्यान श्री मुकेश गहलोत ने बताया कि कृषि शिक्षा में छात्राओं का रुझान ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य योजनान्तर्गत कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राओं को 15 हजार, कृषि स्नातक व स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्राओं को 25 हजार व पीएचडी की छात्राओं को 40 हजार रुपए सालाना छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष स्वीकृत की जाएगी। योजना प्रभारी कृषि अधिकारी कविता गुप्ता ने अवगत करवाया कि छात्रवृत्ति के लिए छात्राएं स्वयं एसएसओ आईडी से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक सम्बन्धित स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के प्रमाणन के साथ कर सकती हैं।

कृषकों का एक दल जैविक खेती प्रशिक्षण के लिए पंतनगर रवाना

श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 संख्या 115 के अनुसार किसानों की क्षमता वृद्धि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से Knowledge Enhancement Programme के अंतर्गत एक प्रशिक्षण दल 40 कृषक को सात दिवस यात्रा अवधि सहित कृषक प्रशिक्षण हेतु गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, उद्यमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) के प्रशिक्षण हेतु कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), श्रीगंगानगर से प्रस्थान किया। उक्त कृषक प्रशिक्षण दल को उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) डॉ. विनोद सिंह गौतम, सहायक निदेशक उद्यान श्री प्रदीप शर्मा, उप परियोजना निदेशक आत्मा श्री सुदेश कुमार, कृषि अधिकारी उद्यान श्री अभिमन्यु गोदारा ने हरी झण्डी दिखाकर बस को रवाना किया। समस्त किसान गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उद्यमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) में विविधिकृत कृषि विषय पर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करेगा साथ ही कृषि कॉलेज तथा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेतों का भी भ्रमण करेंगे तथा कृषकों को विविधिकृत कृषि की सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करवाया जायेगा।

गेहूं खरीद व्यवस्था को लेकर हुई समीक्षा बैठक

श्रीगंगानगर। राज्य में रबी विपणन वर्ष 2026 के अंतर्गत गेहूं की सुचारू, पारदर्शी एवं प्रभावी खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य विभाग के सचिव श्री अम्बरीश कुमार की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी (अनाज) में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में गेहूं खरीद से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री अम्बरीश कुमार ने निर्देश दिए कि सरकारी खरीद के लिए गेहूं लाने वाले किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा आवक के दौरान किसी भी स्तर पर किसानों को असुविधा न हो।

उन्होंने गेहूं की समय पर तौल, मंडी एवं फोकल प्वाइंट पर भंडारित गेहूं को वर्षा व प्रतिकूल मौसम से सुरक्षित रखने, परिवहन एवं हैंडलिंग व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही गोदामों की उपलब्धता, बोरों की भराई, लोडिंग-अनलोडिंग तथा एफएक्यू निर्धारण

(मानव बनाम मशीन) जैसे मुद्दों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में एक ही मंडी अथवा शहर में कार्यरत विभिन्न क्रय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, आढ़तियों एवं किसानों के एजेंसी-वार विभाजन तथा मंडी प्रांगण को एक से अधिक एजेंसियों में विभाजित करने की व्यवहारिक प्रक्रिया पर भी विचार-विमर्श किया गया।

फूड सेक्रेटरी ने खरीद सत्र के दौरान यातायात की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मंडी यार्ड एवं आगमन मार्गों के सुव्यवस्थित ले-आउट एवं मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग एवं एजेंसियां आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि गेहूं खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

बैठक में जिला कलक्टर डॉ. मंजू, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीमति रीना, डीएसओ श्रीमती कविता सिहाग, श्री महिपाल माली, श्री सुरजीत कुमार, क्रय एजेंसियों, मंडी प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कृषक जगत के फेसबुक समर्थक एक लाख के पार

भोपाल (कृषक जगत)। लगातार 80 वर्षों से देश के किसानों को कृषि संबंधी समाचार, सामयिक सलाह, अद्यतन जानकारी और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाला राष्ट्रीय कृषि समाचार पत्र कृषक जगत ने प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कृषक जगत के आधिकारिक फेसबुक पेज पर समर्थकों की संख्या एक लाख के पार हो गई है, जो कृषक जगत के प्रति पाठकों, किसानों और दर्शकों के स्नेह व विश्वास का प्रतीक है।

उल्लेखनीय है कि 1946 में स्थापित कृषक जगत का मूल उद्देश्य किसानों का हित रहा है। यही कारण है कि पिछले आठ दशकों से कृषक जगत किसानों की आवाज बना हुआ है। अतीत से लेकर वर्तमान तक कृषक जगत ने किसानों को कृषि समाचार, सामयिक सलाह, मौसम संबंधी जानकारी तथा कृषि से जुड़ी अद्यतन सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। इसमें कृषि वैज्ञानिकों के लेख, शोध-आधारित सामग्री, त्वरित मार्गदर्शन और नवीनतम जानकारियां शामिल हैं, वहीं किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु एक प्रभावी सेतु के रूप में भी कृषक जगत ने निरंतर भूमिका निभाई है।

समय के साथ तालमेल बिठाते हुए कृषक जगत ने न केवल कृषक जगत पोर्टल की शुरुआत की, बल्कि फेसबुक पर आधिकारिक पेज के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की, ताकि कृषि से संबंधित सूचनाओं का त्वरित और व्यापक प्रेषण संभव हो सके। फेसबुक पेज पर समर्थकों की संख्या का एक लाख के पार पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि किसानों और आमजन ने कृषक जगत की इस डिजिटल पहल को दिल से स्वीकार किया है।

फेसबुक लाइव के माध्यम से कृषक जगत किसान सत्र के अंतर्गत अब तक 100 से अधिक वेबिनार का सफल प्रसारण किया गया, जिन्हें लाखों लोगों ने देखा। इन सत्रों के दौरान कमेंट बॉक्स के जरिए किसानों के प्रश्नों का विषय-विशेषज्ञों द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया। किसान सत्र में आयोजित कृषि ज्ञान प्रतियोगिताओं में सैकड़ों दर्शकों ने भाग लेकर पुरस्कार भी जीते। साथ ही, इस मंच के माध्यम से कई प्रगतिशील किसानों ने सरकारी योजनाओं पर अपने अनुभव, प्रतिक्रियाएं और उपयोगी सुझाव साझा किए।

इस प्रकार यह माध्यम केवल सूचना और ज्ञान का स्रोत ही नहीं रहा, बल्कि सरकारी तंत्र और किसानों के बीच इंटरएक्टिव संवाद का सशक्त मंच भी बना।

विदित है कि कृषक जगत का प्रकाशन संस्थापक द्वय श्री माणिकचंद्र बोंद्रिया और श्री सुरेश चंद्र गंगराड़े के दूरदर्शी नेतृत्व में 1946 में नागपुर से आरंभ हुआ था। मध्यप्रदेश की स्थापना के बाद 1957 में भोपाल से इसका प्रकाशन शुरू किया गया। कृषि को पूर्णत: समर्पित इस समाचार पत्र की बढ़ती लोकप्रियता के चलते 25 वर्ष पूर्व जयपुर से राजस्थान संस्करण और 23 वर्ष पूर्व रायपुर से छत्तीसगढ़ संस्करण का साप्ताहिक प्रकाशन आरंभ किया गया, जिन्हें सराहनीय प्रतिसाद मिला और आज भी दोनों संस्करण निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए कृषक जगत को आईसीएआर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है, जो इसे देश का एकमात्र सम्मानित कृषि समाचार पत्र बनाता है। विकास की इस कड़ी में, वैश्विक कृषि परिदृश्य और कॉर्पोरेट जगत की मांग को देखते हुए दो वर्ष पूर्व अंग्रेजी मासिक पत्रिका 'ग्लोबल एग्रीकल्चर' का प्रकाशन भी शुरू किया गया, जो अल्पकाल में ही देश-प्रदेश के साथ-साथ विदेशों में भी लोकप्रिय हो रही है।

इस उपलब्धि के अवसर पर कृषक जगत परिवार सभी दर्शकों, पाठकों, ग्राहकों, विज्ञापनदाताओं तथा दशकों से जुड़े सभी नाम-अनाम सहयोगियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है। आपका अटूट विश्वास और स्नेह हमें भविष्य में भी नई पहलें, सुविधाएं और किसान-हितैषी पत्रकारिता को और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। पुन: हार्दिक आभार एवं धन्यवाद!

● **सचिन बोन्द्रिया, संचालक**
कृषक जगत

कृषक जगत
डायरी - 2026
बुकिंग प्रारंभ
नए आकार, नए कलेवर में
(एग्जीक्यूटिव डायरी)

कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए संदर्भ ग्रंथ
वर्ष भर कृषि सेवाओं और उत्पादों के
प्रचार हेतु सर्वोत्तम माध्यम

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान कृषि पर विशेष जानकारी
विज्ञापन एवं डायरी खरीदी के लिए संपर्क करें
• इंदौर - सचिन बोन्द्रिया : 9826021837 • भोपाल - अजय बोन्द्रिया : 9826255861
• इंदौर कार्यालय : 9826024864 • रायपुर - प्रेमप्रकाश सुल्लेरे : 9826255862
• नई दिल्ली व जयपुर - निमिष गंगराड़े : 7387422952
• ई-मेल : info@krishakjagat.org • वेबसाइट : www.krishakjagat.org